state-of-the-art fuel efficient passenger cars. This involves a foreign equity participation of *30%* (Rs. 78 crores) on the part of M/s. General Motors Corporation, USA.

Adverse effect of economic liberalisation on small scale industries

654. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem which appeared in the Hindustan Times dated the 9th November, 1992 to the effect that the liberalised economic policies are having a "crippling effect" on the medium and small scale sector units as large scale imports of low value products are pushing smaller units slowly out of market;

(b) whether the All India Manufacturers' Organisation in its study "Dual effect of liberalisation policies and its impact on the medium and small sector" has accused Government of succumbing before the pressure of global lending agencies like the World Bank; and

(c) if so, what are demands of All India Manufacturers' Organisation in this regard and in what manner Government propose to help the smaller units to save them from "unfair world competition" and by "India becoming a dumping ground for goods from the advanced countries" as alleged in the study report of All India Manufacturers' organisation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES) AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. J. KURIEN) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The facts are being ascertained from All India Manufacturers' Organisation.

Poor Collection from Disinvestment of PSU Shares

655. SHRI SURESH KALMADI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a poor collection from the disinvestment of the shares of Public Undertakings during the current financial year;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to review the situation for further disinvestment ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Reconsideration of disinvestment plan for PSU equities

656. SHRI SURESH KALMADI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to reconsider their current disinvestment plans for allowing the public sector undertakings to expand their respective equity base through direct public offers; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTER PRISES) (SHRI P. K. THUNGON) : (a) and (b) The cases of individual enterprise going for expanding their equity base is decided on selective basis and on merits. This does not affect Government's plans for disinvestment of Public Sector shares.

लघु उद्योगों के लिए नई प्रौद्योगिकी

657. श्री महेन्द्र सिंह लाठर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु उद्योगों हेतु नई प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और विकास पर कोई विशेष जोर दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ग) हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में ऐसे कितने लघु उद्योग हैं जो केन्द्रीय सहायता से चलाए जा रहे हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके उत्पादन और निर्यात आदि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान उनके विस्तार, आधुनिकीकरण और उनके द्वारा नई प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता/अनुदान का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) जी, हां ।

(ख) आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत् लघु उद्योग सेवा संस्थानों के माध्यम से अधिक चुने स्थानों/समूहों के विशिष्ट अध्ययन करके आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन का एक पुनः अभिमुख कार्यक्रम आरम्भ किया गया है । चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों में लगभग 25 समूह अध्ययन करने का प्रस्ताव है ।

प्रौद्योगिकियों के विकास तथा उन्हें अपनाने के लिए सरकार ने लघु उद्योगों के लाभ के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न औजार कक्ष तथा प्रशिक्षण केन्द्र, प्रक्रिया तथा उत्पाद विकास केन्द्र और विशिष्ट संस्थान स्थापित किए हैं ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सहायता से कोई लघु एकक नहीं चलाया जा रहा है ।

गुजरात में खादी ग्रामोद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

658. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने गुजरात में खादी ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कोई योजना बनाई है ।

(ख) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान इस प्रयोजन के लिए कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकासार्थ नयी योजनाओं सहित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में गुजरात राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के. वी. आई. सी.) द्वारा किया जाता है । राज्य बोर्ड के साथ हुई अपनी बजट चर्चाओं के अनुसार सहमति प्राप्त कार्यक्रमों के आधार पर के. वी. आई. सी. अनुदान और ऋण के रूप में गुजरात राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को वित्तीय सहायता प्रदान करता है । के. वी. आई. सी. ने गुजरात सहित देश के पहाड़ी, सीमावर्ती, जनजातीय क्षेत्रों तथा कमजोर वर्गों के लिए भी वित्तीय सहायता की योजनाएं और प्रतिमान तैयार किए थे ।

खादी तथा ग्रामोद्योग संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को दी गयी धनराशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(लाख रुपयों में)

	दी गयी धनराशि	
	अनुदान	ऋण
खादी	400.15	59.51
ग्रामोद्योग	31.56	58.91
योग	431.71	118.45

Closing down of Sick PSU

659 SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the Union Government propose to close down/privatise 47 chronically sick Central Public Sector Undertakings as